

संपादकीय

जाति, गणना और चुनाव

लं बे समय से सियासी जगत में जाति आधारित बिहार ने इसे नया मोड़ दे दिया है। उसने अपने स्तर पर जनगणना कराकर नतीजे भी जारी कर दिये हैं। जबकि लंबे समय से इस तहके के नतीजे जारी करने से परहेज ही रखा जा रहा था। अब इस मामले को यूथ और देखा जा सकता है कि चाहे सतर के दशक में आपातकाल के खिलाफ जेंटी आंदोलन हो या नव्वे के दशक में शुरू हुई मंडल राजनीति रही हो, बिहार ने दोनों मौकों पर बदलाव की अगुआई की थी। अब जब पिछले करीब एक दशक से देश में कथित सेक्युलर राजनीति को विस्थापित करती हुई राष्ट्रवादी राजनीति हावी दिख रही थी, जाति आधारित गणना के नतीजों के रूप में बिहार ने ऐसा धमाका किया है, जिसके अंदर चुनावी राजनीति के समीकरण बदलने का मादा है। खैर, अभी तो सब इसी गणना में लगे हैं कि अगर पिछड़े और

अति पिछड़े मिलकर राज्य की आबादी का दो तिहाई हो जाते हैं तो फिर इसको काट के तौर पर दूसरा कौन सा समीकरण पेश किया जा सकता है। चूंकि बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, तो अब केंद्र की भाजपा सरकार का यह तर्क निर्भक हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। अपर्याप्त में तो कांग्रेस नेता कह भी चुके हैं कि वे ऐसी गणना कराएं। अब हाँ तरफ से यहीं सवाल उठाया कि जब एक राज्य में संभव हो गया तो दूसरे राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी वह काम क्यों नहीं हो सकता। चूंकि इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब उपलब्ध नहीं है, इसलिए भाजपा नेताओं

का भी मुख्य स्वर यहीं हो गया है कि वे जाति आधारित गणना के खिलाफ नहीं हैं और बिहार सरकार के फैसले में भी शुरू से शामिल रहे हैं। लेकिन सबल यह है कि जातिगत जनगणना के मसले पर पॉजिटिव रुख देखाकर भाजपा क्या इडिया गढ़वालने के मुकाबले बढ़ाव बना पाएगी? अक्सर ऐसा होता है कि जिस मुद्रे पर जिसने शुरूआत की, उसे उसका लाभ भी तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। जाति जनगणना के मामले में यह काम जेंडीयू और आरजेडी ने किया है, जो भाजपा के खिलाफ बन कांग्रेस समेत तमाम दलों वाले गढ़वालन का मुख्य हिस्सा है। मगर इसके साथ यह भी याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री नें दो मोदी देश के

लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। ऐसे में किसी भी चुनाव में मोदी फैटकर की अनदेखी नहीं की जा सकती। मगर क्या यह मुद्रा चुनाव तक प्रासारित करना रहेगा। राजनीति में तो एक सप्ताह का वक्त भी लंबा माना जाता है, ऐसे में छह महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव तक बहुत कुछ बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मोदी ने कहा भी है कि संचाला में हिंदू सभ्यता ज्यादा हैं तो क्या वे आगे आकर सभी हक्क ले लें। वहीं दूसरी बात यह कि 2023 का भारत नब्बे के दशक के भारत से अलग है। जाति आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वह हमारी आजीविका, सोच और खासकर वैज्ञानिक विवेचिकों को उस तरह से प्रभावित नहीं करती, जैसे नव्वे के दशक में करती थी। इसलिए देखना होगा कि यह मुद्रा लोगों तक किस रूप में पहुंचता है, और जातीय गणित से आगे इसकी केमिस्ट्री किस तरह से विकसित होती है। मगर यह भी तय है कि अनेक वाले राज्यों के विस चुनाव और लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आकर ठहर रहा है।

निशाना

सो रहा है तंत्र !



नससंहार हो रहे।
सो रहा है तंत्र ॥
कसने समय पर ।
दिया गया है मंत्र ॥
ये कैसे हैं अल्पाचार ।
लील रहे जान ॥
अबला और मासूमों पर ।
टूट पड़े शैतान ॥
मानतावा है शर्मसा ।
ये कैसे कर डाला ?
भनक उनको ना लगी ।
जो बनते रखवाला ॥
बंद न होती घटनाएं ।
होता ना सुधा ॥
ना बतलाता कर्दे ।
हो कैसे उपचार ?
- कृष्णन्द्र राय-

आज का इतिहास

- 1997 - क्रिकेट ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को हुआ था।
- 1857 - भारतीय क्रांतिकारी सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय देशभक्त, वकील और पत्रकार थे। जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था।
- 1884 - रामचंद्र शुक्ल व्यापक, शोध का उपयोग करके हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले सहिती अनुपात होती है। इसका उद्देश्य विश्वभूमि के शिक्षकों के जीवन में खोड़ी-सी भूल रही जाती है तो समाज, राष्ट्र एवं विश्व के निर्माण की नींव खोली रही जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण इकाई संयुक्त राष्ट्रीयक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विश्व शिक्षक दिवस की शुरूआत 5 अक्टूबर, 1994 को गयी थी। इसका उद्देश्य विश्वभूमि के शिक्षकों के जीवन निर्माण में दिये जा रहे महत्वपूर्ण योगदान पर विचार-विमर्श के लिए कृत संकलित है। प्राचीन समय से भारत शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है और उसने संसार में जगतगुरु की भूमिका निर्मायी है।
- 1980 - एस.के. ओझा एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे। जिनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 1980 को हुई थी। आरक्षण से तब फर्क पड़ता है, जब

जातिगत सर्वे के सामाजिक-आर्थिक पहलू, उम्मीद पूरी नहीं कर सका टॉप-डाउन का विकास मॉडल

प्रो. अरुण कुमार

हाँ में जातिगत सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं और इन आंकड़ों के सामने आते ही पूरे देश में इसको लेकर सियासत गरम गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सर्वे के अंतर्गत गणना की मांग की जा रही है और कनार्टक में 2015 में हुए जातिगत सर्वे के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी है। बिहार में हुए सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ी वर्ग की है, जो कूल आबादी के करीब 36 फीसदी है। इससे बिहार की स्थिति का तो पता चल रहा है, लेकिन पूरे देश में क्या स्थिति है, वह भी पता चलना चाहिए। लिहाजा, अब केंद्र सरकार पर यह दबाव बढ़ जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े तैयार करके सार्वजनिक करें, ताकि कूल आबादी में जातिगत अनुपात का पता चल सके, जिससे उनके नामके राज्यों में बेहतर हिस्सेदारी के लिए आवश्यक नीतियां बनाई जा सकें। बिहार की कूल आबादी में अत्यंत पिछड़ी वर्ग का अनुपात बढ़ रहा है, जो स्थापात्का लगता है। इसकी वजह यह है कि अत्यंत पिछड़ी वर्ग में गरीबी ज्यादा है। जो गरीब होते हैं, वे शिक्षा का जीवन की कमी तथा बुड़ापेट में अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए जातिगत सर्वे के आंकड़ों को नाकरियां करते हैं। गरीबों के पास बचत तो होती नहीं, ऐसे में बच्चे ही उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का आधार होती है। वे हो सकते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे, तो ज्यादा कमाकर लाएंगे और बुड़ापेट में उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन जातिगत सर्वे के आंकड़ों को अंतर्गत गणना की मांग बढ़ जाएगी। मेरा मानना है कि अगर हम शुरू से ही अत्यंत पिछड़ी जातियों को रोजगार और शिक्षा में ज्यादा तरह दें, तो आज जो यह स्थिति आई है, वह नहीं आई होती। अगर रोजगार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, तो आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरक्षण से तब फर्क पड़ता है, लेकिन ट्रैक्टर, कंबाइन



सभी राजनीतिक पार्टियां इसका अपने-अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहेंगी और देश में एक बार फिर से मंडल-क्रमांकित राजनीति और बढ़ जाएगी। लेकिन भाजपा के लिए इसी राजनीतिक सर्वे के विरोधी यह तर्क देते हैं कि इस तरह के सर्वे के आंकड़ों में जिन जातियों की संख्या कम होती है, वे परिवार में समृद्धि बढ़ती है, लेकिन भाजपा के अनुचित नामान्तर के लिए लिए गए राजनीतिक नामान्तर को अपनाए हैं और अब यह भी मांग उठेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। दुनिया भर में जैसे-जैसे परिवार में समृद्धि बढ़ती है, तो सर बढ़ता है, लोग परिवार नियोजन को अपनाते हैं और कम बच्चे पैदा करते हैं। कम आबादी वाले समृद्ध परिवारों के लोग अपने बच्चों के अधिकार को अपनी आबादी बढ़ाने की होती में लगा रहाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। दुनिया भर में जैसे-जैसे जिन जातियों को अपनाए हैं और अब यह अब भी हो रहा है। बिहार के जातिगत सर्वे के आंकड़ों के राजनीतिक निहितार्थ तो स्पष्ट हैं ही और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ना लाजिमी है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसका अपने-अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहेंगी और देश में एक बार फिर से मंडल-क्रमांकित राजनीति और बढ़ जाएगी। लेकिन भाजपा के लिए इसी राजनीतिक सर्वे के आंकड़ों में जिन जातियों को अपनाए हैं और अब यह भी मांग उठती है। आरक्षण की अधिकतम निहितार्थ तो स्पष्ट हैं ही और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ना लाजिमी है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसका अपने-अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहेंगी और देश में एक बार फिर से मंडल-क्रमांकित राजनीति और बढ़ जाएगी। लेकिन भाजपा के लिए इसी राजनीतिक सर्वे के आंकड़ों में जिन जातियों को अपनाए हैं और अब यह भी मांग उठती है। आरक्षण की अधिकतम निहितार्थ तो स्पष्ट हैं ही और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ना लाजिमी है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसका अपने-अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहेंगी और देश में एक बार फिर से मंडल-क्रमांकित राजनीति और बढ



विकास किया है विकास करेंगे



लाइली बहनों को
बढ़ाकर ₹ 1250 की किश्त का
सिंगल क्लिक से वितरण



मुख्यमंत्री
रिपब्लिक सिंह चौहान

द्वारा

बुरहानपुर, अपराह्न 12.30 बजे

तथा

ग्लोबल स्किल्स पार्क
जबलपुर, गयालियट, सागर एवं दीया का
शिलान्यास
एवं
9 संभागीय आईटीआई
का लोकार्पण

मेडिकल कॉलेज
बालाघाट, धाट, मुर्दैना, भिंड एवं मंडला
तथा
विधि कॉलेज बालाघाट
का भूमिपूजन
बालाघाट, अपराह्न 3:30 बजे

मुख्यमंत्री सीएपो-कमाओ योजना

प्रथम स्टायर्पेंड वितरण तथा
आईटी पॉलिसी का विमोचन
भोपाल, रात्रि 8:00 बजे

4 अक्टूबर, 2023



मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना

- अक्टूबर से बहनों को मिलने लगे ₹ 1250
- बहनों के समान में लागू इस योजना से बहने बन रहीं
सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त, बच्चों को मिल रहा
बेहतर स्वास्थ्य और पोषण, अब तक मिले ₹ 6808 करोड़

मुख्यमंत्री सीएपो-कमाओ योजना

- युवाओं में कौशल विकास के साथ उन्हें रोजगार से जोड़ने के
लिए लागू इस योजना में 8 से 10 हजार रुपये तक स्टायर्पेंड
- 9 लाख से अधिक युवा पंजीकृत, 74 हजार से अधिक
वैकेन्सी हुईं क्रिएट, 19 हजार से अधिक प्रतिष्ठान पंजीकृत।

मेडिकल कॉलेज

- मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2002-03 में
5 से बढ़कर वर्ष 2023 में हुई 30
- चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए मेडिकल
की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ

ग्लोबल स्किल्स पार्क

- युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी एवं
व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध
- बढ़ रहे रोजगार और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर